विमुद्रीकरण की सालगिरह

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(08 नवंबर, 2017)

सुरजित एस भल्ला
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

आज एक अभूतपूर्व और बोल्ड राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग डीएम (DM) अर्थात विमुद्रीकरण की पहली सालगिरह है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बातें है कि यह एक अनावश्यक, गैरजिम्मेदाराना और बेकार प्रयोग था, जिसकी लागत अधिक और लाभ काफी कम थी। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि विमुद्रीकरण एक महंगा और अप्रभावी प्रयोग था। अभियोग तर्क जो केवल अनुभवजनों द्वारा गलत साबित हो सकता है। अब हम सबूतों के बारे में बात करते हैं। इस आलेख में दिए तालिका में विमुद्रीकरण के पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के सन्दर्भ में कुछ तथ्य दिए गये हैं। विमुद्रीकरण के बाद की अवधि अर्थात अप्रैल से सितंबर 2017 तक है और विमुद्रीकरण के पहले की अवधि पिछले वर्ष की यही अवधि है। कुछ डेटा (उदाहरण के लिए, रोजगार पर सीएमआईई डेटा) अगस्त तक ही उपलब्ध है और इस तरह के आंकड़ों के लिए पिछले वर्ष जनवरी-अगस्त के साथ तुलना की गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे एक साल पहले सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले के विरोध में आठ नवंबर को काले दिन के रूप में मनाएंगे। नोटबंदी की तारीख को कांग्रेस ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी के वक्त कहा गया कि काला धन खत्म होगा, नकली नोट, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगेगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 99% पैसा वापस आ गया। लेकिन मोदी द्वारा कही गयी कोई भी बात पर अब तक सही साबित नहीं हुई है।

विकास मंदी - मुक्ति की वजह से?

जैसा कि कई ने उल्लेख किया है, जीडीपी विकास मंदी की शुरुआत नवंबर, 2016 से पहले हुई थी। लगातार दो तिमाहियों, अर्थात 2015 क्वाटर 4 और 2016 क्वाटर 1 के लिए 10.3% तक रहा, लेकिन बाद में औद्योगिक विकास, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के खातों द्वारा मापा गया, सितंबर 2016 तक दर (5.9%) के करीब आधा हो गया। अगर कोई तालिका में औद्योगिक विकास और ऋण वृद्धि संख्या को देखता है, तो वह अर्थव्यवस्था की एक बहुत बुरी हालत को देख पायेगा और यह दुख की बात है। उद्योग जो जीडीपी के लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है, अब कुछ समय से रेंग रहा है। आरबीआई / एमपीसी द्वारा इस स्थिति को त्वरित और प्रोत्साहित किया गया है, जिसके कारण वास्तविक नीति दरों दिसंबर, 2016 में 1.1% से बढ़कर सितंबर 2017 में 3% हो गयी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ब्याज दरें मांग को प्रभावित करती हैं और फिर उत्पादन को। विमुद्रीकरण की वजह से विकास में कमी के बारे में टिप्पणी करने वाले सभी लोगों से मेरी दलील है कि वे अनगिनत गरीब और अमीर लोगों के लिए एक आँसू बहाना छोड़ दें, जो उच्च ब्याज दर नीति द्वारा काफी गरीब बना चुके हैं। और ध्यान दें कि वर्ष के दौरान एमपीसी संचालन में रहा है, सीपीआई मुद्रास्फीति की औसत औसतन 3.1% है।

सभी नकद वापस आ गया है, इसलिए विमुद्रीकरण विफल रहा?

विपक्षी राय की एक पसंदीदा तर्क यह है कि विमुद्रीकरण विफल हो गया, क्योंकि सभी नकदी प्रणाली में वापस आ गए। लेखक के विचार में, यह बहुत सकारात्मक है कि सभी नकद वापस आ गये, क्योंकि अब काला धन काले रंग के रूप में पहचाना जा सकता है। यह कर अधिकारियों पर निर्भर है और वैध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अगर केवल आयकर अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के साथ होंगे तो भी विमुद्रीकरण एक बड़ी सफलता साबित होगी। हर कोई जानता है कि भारतीय कर अधिकारियों को कर चोरी के लिए सहकर्मी रहना पड़ता है, क्योंकि वे भारत में हैं। यदि वे बदलते हैं, तो भारत बेहतर और इसका विकास तेज हो जाएगा

टैक्स अनुपालन

इस वित्त वर्ष (अप्रैल से सितंबर) के लिए डेटा का सुझाव है कि टैक्स अनुपालन में काफी वृद्धि हुई है। टैक्स अनुपालन दो भागों से बना है- नए करदाता और पुराने करदाता, जो कम कर चोरी करते हैं। अगर पुराने करदाता अब, विमुद्रीकरण के बाद काफी अधिक भुगतान करते हैं, तो विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे रचनात्मक और बोल्ड कदम हो सकता था। (गहनता से और इस पर एक और दिन चर्चा की जानी है, ब्याज दरों जैसे कर दरों को दोनों इक्विटी और दक्षता के कारणों के लिए बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।)

Demonetisation gains

April-September rates of growth

	Pre-DM 2016	Post-DM 2017
Monetary policy & its discontents		
Real repo rate (levels)	1.1	3.7
Credit-industry*	0.4	-1
CPI	5.4	2.6
IIP**	5.8	2.2
Demonetisation & its economic effects		
Tax compliance		
Gross total revenue	16.6	19.9
Direct tax revenue	8.5	13.5
Indirect tax revenue	25	25.6
Towards a 'cashless' economy		
Cash withdrawn from ATMs	16	-8.3
Total digital transactions	23.5	39.5
Cards at POS	34.8	82.7
Prepaid + mobile	72.9	177.7
Good news puzzles of the Indian economy		
Rural wages		
Agricultural	0.1	4.9
Non-agricultural	-1.3	3.4
Rural unemployment rate[#] (level)		
Age-group 15-64	8.4	4
Age-group 25-64	2.9	1.7
Change in total employment[#]		
Age-group 15-64 (in mn)	-	6
Age-group 25-64 (in mn)	-	12.7

फरवरी में अपने विमुद्रीकरण के बाद के बजट में, वित्त मंत्रालय ने 11.8% की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर और प्रत्यक्ष कर संग्रह (व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट टैक्स) को 15.6% से बढ़ने का अनुमान लगाया था। दुर्भाग्य से, और अल्ट्रा-तंग मौद्रिक नीति की मदद से, अप्रैल-जून 2017 के दौरान नाममात्र साल-दर-साल जीडीपी विकास (मूल कीमतों पर जीवीए विकास) केवल 7.9% था, जो रिकॉर्ड के 6 सबसे कम (1996 के बाद से) में से

एक था। यहां तक कि इस कम, निम्न आय वृद्धि के साथ, प्रत्यक्ष कर राजस्व 13.5% की गति से बढ़ गया है, जो लक्षित 15.6% के करीब है। यह करीबी पत्राचार केवल तब संभव हुआ जब कर अनुपालन में बड़ी वृद्धि हुई।

यह कर अनुपालन में बड़ी वृद्धि का एकमात्र उपाय है जिसे पहले भी देखा जा चुका है। और भी अधिक परिणाम आने बाकी है और यदि विमुद्रीकरण की वजह से भारत, इस वित्तीय वर्ष की तुलना में, इस वर्ष की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष कर राजस्व के साथ समाप्त होता है, तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है।

विमुद्रीकरण के बारे में पहेलियाँ

पहली पहेली यह है कि सबसे पहले ग्रामीण भारत में वास्तविक मजदूरी वृद्धि का पैटर्न है। वास्तविक कृषि मजदूरी (श्रम मंत्रालय नाममात्र वेतन से कम ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति) 2016 में (जनवरी-जुलाई) 0.1% और 2017 में एक मजबूत 4.9% की वृद्धि हुई; गैर-कृषि ग्रामीण मजदूरी एक ही पैटर्न दिखाते हैं, 2016 में एक 1.3% की गिरावट और 2017 में 3.4% की वृद्धि हुई।

दूसरी पहेली भारत में रोजगार और बेरोजगारी का पैटर्न है। भारत के लिए हाल ही में उपलब्ध रोजगार डेटा एक निजी डेटा कंपनी, सीएमआईई द्वारा जारी किया है। इन आंकड़ों के आधार पर, जुलाई के मध्य में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 2017 के पहले चार महीनों में 1.5 मिलियन नौकरियां खोई थीं। इस रिपोर्ट को इस सबूत के रूप में उठाया गया था कि विमुद्रीकरण निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से शीर्षक और विश्लेषण गलत-अग्रणी है। यहाँ लेखक ने सितंबर-दिसंबर 2016 और जनवरी-मार्च 2017 के बीच रोजगार में बदलाव की तुलना की थी। सौभाग्य से, सीएमआईई डेटा (उनकी वेबसाइट पर पोस्ट की गई) जनवरी-अगस्त 2016 (पूर्व- विमुद्रीकरण) और जनवरी-अगस्त 2017 (विमुद्रीकरण के बाद) के बीच की तरह, जैसे नौकरी (और बेरोजगारी आदि) जैसी तुलना करने के लिए अनुमति देता है।

परिणाम (सुखद) चौंकाने वाला है। रोजगार की संख्या में विमुद्रीकरण के बाद वृद्धि हुई है, जहाँ 15-24 वर्ष की आबादी के लिए रोजगार में 7 मिलियन की वृद्धि हुई, और 25-64 आयु वर्ग के लिए, 12.7 मिलियन या 3.7% की वृद्धि दर, जो कि पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक (पिछले साल, एनएसएस डेटा) है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दिलचस्प समय हैं। जहाँ राजनीतिक और आर्थिक मामले में बहुत सारे परिवर्तन हुए है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी करना बेबकूफी होगा।

संबंधित तथ्य

विमुद्रीकरण: जब कोई सरकार अपने यहाँ प्रचलित किसी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इस प्रिक्रिया को विमुद्रीकरण (demonetization) कहा जाता है।

- विमुद्रीकरण के पश्चात उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उस मुद्रा की वैध मान्यता समाप्त हो जाती है।

क्यों? : उल्लेखनीय है कि सरकार ऐसा कई कारणों से कर सकती है:

- मुद्रा की जमाखोरी को खत्म करने के लिये,
- आतंकवाद, अपराध तथा तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये,
- बाजार में प्रचलित नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिये, तथा
- कर चोरी हेतु किये जाने वाले नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिये।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था।
- ध्यातव्य है कि देश में अभी तक 10 हजार रुपए से अधिक का नोट जारी नहीं किया गया है।
- 1970 के दशक में प्रत्यक्ष कर की जाँच से जुड़ी 'वानचू कमिटी' ने काले धन को बाहर लाने के लिये विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन इस सुझाव के सार्वजनिक हो जाने की वजह से काला धन रखने वालों ने अपने पास उपलब्ध धनराशि का तत्काल प्रबंधन कर लिया था।
- हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब देश में नोटबंदी की गई हैं, इससे पहले भी वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने एक कानून के माध्यम से 1000, 5000 तथा 10,000 के नोटों को बंद कर दिया था।

कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम?

- किसी भी अर्थव्यवस्था का कैशलेस होना एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। जैसा कि सम्भावना व्यक्त की जा रही थी, विमुद्रीकरण भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के लिये तैयार है?
- देश की एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है जिसके पास कोई भी बैंक खाता नहीं है, हालाँकि इस सरकार की महत्त्वाकांक्षी जन-धन योजना में बड़े पैमाने पर खाते खोले गए, लेकिन अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग बैंकिंग सुविधाओं से दूर है। साथ ही, यह भी सत्य है कि बिना स्मार्टफोन के एक बड़ी आबादी के लिये इस नई व्यवस्था से जूझना काफी मुश्किल होगा।

संभावित प्रश्न

देश में कालेधन को वापस लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था। इसके बावजूद विमुद्रीकरण कालेधन को वापस लाने में असफल रहा है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? साथ ही इस निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा? उसकी भी चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The decision of demonetization was taken by the government for the purpose of bringing back black money to the country. Despite this, demonetization has failed to bring back black money. Where do you agree with this statement? Also discuss the consequences of this decision on the Indian economy. (200 words)